भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2793
(जिसका उत्तर मंगलवार,17 मार्च, 2026/26 *फाल्गुन,* 1947 (शक) को दिया जाना है)

घरेलू बचत में गिरावट और आर्थिक स्थिरता पर इसके प्रभाव

2793. **श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने हाल के वर्षों में भारत में घरेलू बचत दर में महत्वपूर्ण गिरावट का संज्ञान लिया है, जिसमे वित्तीय संकेतक यह दर्शाते हैं कि जीडीपी में बचत का हिस्सा बहुत कम हुआ है;
(ख) पिछले पांच वर्षों के लिए, वित्तीय और गैर-वित्तीय बचत तथा ऋण के उपयोग सहित, घरेलू बचत और देयताओं के वर्ष-वार आंकडे क्या हैं; और
(ग) दीर्घकालिक निवेश, परिवारों के वित्तीय मजबूती और भविष्य की विकास दर पर इसके प्रभाव के संदर्भ में क्या इस प्रवृत्ति के व्यापक आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का आकलन क्या किया गया है, और बचत को सुदृढ़ करने और ऋण पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए कौन-कौन से सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
वित्त राज मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क)और (ख) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी जीडीपी अनुमानों (आधार वर्ष 2022-23) की नई श्रृंखला के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में घरेलू बचत 2022-23 में 20.0 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 21.7 प्रतिशत हो गई है। वित्तीय और गैर-वित्तीय बचत के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों के लिए घरेलू देयताओं सहित घरेलू बचतों का वर्ष-वार विवरण, जिसके लिए नई श्रृंखला के तहत डेटा उपलब्ध है, नीचे दिया गया है।

वित्त वर्ष	घरेलू बचत	घरेलू वित्तीय बचत	घरेलू गैर-वित्तीय बचत (*)	घरेलू वित्तीय देयताएँ
				(लाख करोड़ रुपये में)
2022-23	52.2	29.8	38.4	16.0
2023-24	59.6	35.8	42.7	18.8
2024-25	69.0	38.3	46.4	15.7
				(जीडीपी का प्रतिशत)
2022-23	20.0	11.4	14.7	6.1
2023-24	20.5	12.3	14.7	6.5
2024-25	21.7	12.0	14.6	4.9

नोट: * गैर-वित्तीय घरेलू बचत में भौतिक परिसंपत्तियों में बचत और सोने और चांदी के आभूषणों के रूप में बचत शामिल है।

ग) घरेलू बचत अर्थव्यवस्था में निवेश के वित्तपोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और परिवारों के वित्तीय लचीलेपन को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाल के वर्षों में, सरकार ने व्यापार करने में सुगमता में सुधार, कौशल पहलों का विस्तार करने, रोजगार सृजित करने, समावेशी मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देने और अवसंरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से नीतियां शुरू की हैं, जिससे घरेलू आय और बचत में निरंतर वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय के लिए आयकर छूट और जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने जैसे हालिया नीतिगत उपायों से प्रयोज्य आय में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे मध्यम अवधि में उच्च घरेलू खपत, बचत और निवेश को समर्थन मिलेगा और इस प्रकार, ऋण पर निर्भरता कम होगी।

*****